भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3438
गुरुवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास

3438. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में सैद्धांतिक अनुमोदन और स्थल स्वीकृति प्राप्त ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की राज्य-वार स्थिति क्या है और उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या हैं जिनका देश भर में प्रचालन हो रहा है, निर्माणाधीन और प्रस्तावित हैं;

(ख) पुरी, ओडिशा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की वर्तमान स्थिति क्या है तथा भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय और सांविधिक मंजूरी, अनुमानित परियोजना लागत, वित्तपोषण पद्धति और निर्माण कार्य शुरू करने और पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से ओडिशा में तीर्थयात्रा और तटीय पर्यटन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित पुरी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से होने वाली यात्रियों की मांग, पर्यटन में वृद्धि और क्षेत्रीय संपर्क लाभ का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और पीपीपी आधारित परियोजनाओं सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत ओडिशा में विमानपत्तन अवसंरचना के विकास के लिए कितना पूंजीगत व्यय किया गया/किए जाने का विचार है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) **:** ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति के तहत, देश भर में 24 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए "सैद्धांतिक" मंजूरी दी गई है, अर्थात् ओडिशा में पुरी, तमिलनाडु में पारंदूर, राजस्थान में कोटा, गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलबुरगि, विजयपुरा, हसन और शिवमोग्गा, मध्य प्रदेश में डबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और राजकोट (हीरासर), पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगदार्थी, भोगापुरम और ओरवाकल (कुर्नूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर। इनमें से 13 ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे अर्थात दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कलबुरगि, ओरवाकल (कुर्नूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोग्गा, राजकोट (हीरासर) और नवी मुंबई में परिचालन शुरू हो गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने 7 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों नामत: राजस्थान में अलवर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, हिमाचल प्रदेश में मंडी, केरल में कोट्टायम, असम में डोलू, कर्नाटक में रायचूर और बिहार में सोनपुर के निर्माण के लिए 'साइट क्लीयरेंस' भी दे दी है।

(ख) और (ग): नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 06.05.2025 को पुरी में अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए ओडिशा राज्य सरकार (जीओओ) को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है।

जीएफए नीति के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर, वित्त पोषण, पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने आदि सहित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता या राज्य सरकार की है, जैसा भी मामला हो। हवाईअड्डा परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा, भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।

हवाईअड्डे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालते हैं। हवाईअड्डों के विकास से यात्रियों की आवाजाही, पर्यटन विकास, रोजगार सृजन में वृद्धि होती है और भूमि मूल्यांकन की सर्कल दरों में वृद्धि होती है, जिससे संबंधित राज्य में विभिन्न करों/स्टांप शुल्क आदि के संग्रह में वृद्धि होती है और देश का समग्र विकास होता है। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के अध्ययन से पता चलता है कि हवाई संपर्क का आर्थिक गुणक 3.25 और रोजगार गुणक 6.1 है।

(घ): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 (फरवरी 2026 तक) के दौरान ओडिशा में हवाई अड्डों के विकास के लिए 479 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

******